कुलेश मंडल

बनाम

पश्चिम बंगाल राज्य

7 सितंबर, 2007

(डॉ. अरिजीत पासायत और डी. के. जैन, जे. जे.,)

दंड संहिता, 1860ः

धारा. 300, अपवाद 4- प्रयोज्यता: प्रतिपादित - अपवाद 4 के प्रयोजन के लिए, यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्वधारणा नहीं थी-यह आगे दिखाया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया या क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया।

धारा. 300, अपवाद 4, एसएस। 304 भाग 1 और 302-अचानक लड़ाई के दौरान एक तेज धार वाले हथियार से गर्दन पर घातक प्रहार-न्यायालयों द्वारा एस. 302 में दोषी ठहराया गया - तथ्यों के बारे में कहा गया: अपवाद 4 से एस. 300 लागू होता है - अपराध एस. 304 भाग प् से जोड़ा ओर न की एस 302।

धारा. 300 , अपवाद 1 और 4-के बीच का अंतर-समझाया गया।

साक्ष्यः

करीबी रिश्तेदार का साक्ष्य-इसे पक्षपातपूर्ण होने के एकमात्र आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

साक्ष्य में विसंगति-सामान्य विसंगति और सारभूत विसंगति-के बीच का अंतर-बताया गया।

शब्द और वाक्यांश-''लड़ाई'', ''अचानक लड़ाई'' और ''अनुचित लाभ'' का अर्थ- आईपीसी के एस. 300 के अपवाद 4 के संदर्भ में।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक झगड़े के दौरान, अपीलार्थी का भाई मृतक को घटना स्थल पर घसीट कर ले गया जिसके बाद अपीलार्थी ने एक तेज धार वाले हथियार 'हसुआ' से उसकी गर्दन पर घातक प्रहार किया। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को एस 302 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलार्थी की दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि चश्मदीद गवाह पीड़ित से संबंधित थे और इसलिए उनकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सका और चूंकि झगड़े के दौरान केवल एक ही वार दिया गया था, एस. 302 आईपीसी प्रयोज्य नहीं।

न्यायालय द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार।

अभिनिर्धारित: 1. यह आधार कि गवाह करीबी रिश्तेदार हैं और नतीजतन, पक्षपातपूर्ण गवाह होने पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, इसका कोई आधार नहीं है। (पैरा 7), (804-ई),

दलीप सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, एआईआर (1953) एससी 364; मसलती और अन्य बनाम. उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर (1965) एससी 202; पंजाब राज्य बनाम जागीर सिंह, एआईआर (1973) एससी 2407; लेहना बनाम हरियाणा राज्य, (2002) 3 एससीसी 76 और राजस्थान राज्य बनाम श्रीमती. कल्कि और अन्य, एआईआर (1981) एससी 1390 पर निर्भर था।

2. साक्ष्य में सामान्य विसंगतियाँ वे हैं जो होती हैं सामान्य अवलोकन की त्रुटियाँ, समय बीतने के कारण स्मृति की सामान्य त्रुटियाँ, घटना के समय सदमे और भय जैसे मानसिक स्वभाव के कारण और वे हमेशा होती हैं, हालांकि एक ईमानदार और सच्चा गवाह हो सकता है। सारभूत विसंगतियाँ वे हैं जो सामान्य नहीं हैं, और एक सामान्य व्यक्ति से अपेक्षित नहीं हैं। न्यायालयों को उस श्रेणी को चिह्नित करना होगा जिसमें विसंगति को वर्गीकृत किया जा सकता है। जबकि सामान्य विसंगतियाँ किसी पक्ष के मामले की विश्वसनीयता को कम नहीं करती हैं, सारभूत विसंगतियाँ ऐसा करती हैं। (पैरा 9), (805-डी-ई),

कृष्ण मोची और अन्य बनाम बिहार राज्य आदि, जेटी (2002) 4 एससी 186, आश्रित पर।

3.1. आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 को लागू करने के लिए, इसने यह स्थापित करने के लिए कि यह कार्य बिना पूर्व-चिंतन के किया गया था, अचानक झगड़े पर आवेश के वेग में अचानक लड़ाई में अपराधी ने अनुचित लाभ उठाए बिना और क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया था। (पैरा 11), (805-एफ),

3.2. आईपीसी की धारा 300 के चैथे अपवाद में अचानक लड़ाई में किए गए कार्य शामिल हैं। उक्त अपवाद अभियोजन के एक मामले से संबंधित है, जो पहले अपवाद के दायरे में नहीं आता है, जिसके बाद इसका स्थान अधिक उपयुक्त होता। अपवाद एक ही सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोनों में पूर्वचिन्तन का अभाव है। लेकिन, जबकि अपवाद 1 के मामले में आत्म-नियंत्रण का पूरी तरह से अभाव है, अपवाद 4 के मामले में, केवल आवेश का वेग है जो पुरुषों की शांत बुद्धि को प्रभावित करती है और उन्हें ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित करती है जो वे अन्यथा नहीं करेंगे। अपवाद 4 में उत्तेजना है जैसा कि अपवाद 1 में है, लेकिन की गई चोट उस उत्तेजना का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। वास्तव में अपवाद 4 उन मामलों से संबंधित है जिनमें भले ही कोई वार लगा हो, या विवाद की उत्पत्ति में या किसी भी तरह से झगड़ा उत्पन्न हुआ हो, फिर भी दोनों

पक्षों का बाद का आचरण उन्हें अपराध के संबंध में समान आधार पर रखता है। एक 'अचानक लड़ाई' का अर्थ है आपसी उकसावे और दोनों पक्षों पर मार-पीट। तब की गई हत्या स्पष्ट रूप से है एकतरफा उकसावे के लिए पता नहीं लगाया जा सकता है, और न ही ऐसे मामलों में पूरे दोष को एक तरफ रखा जा सकता है। यदि ऐसा था, तो अधिक उचित रूप से लागू होने वाला अपवाद अपवाद 1 होगा। कोई पूर्व विचार-विमर्श या लड़ने का दृढ़ संकल्प नहीं है। अचानक एक लड़ाई होती है, जिसके लिए दोनों पक्षों को कमोबेश दोषी ठहराया जाता है। यह हो सकता है कि उनमें से एक ने इसे शुरू किया हो, लेकिन अगर दूसरे ने इसे अपने स्वयं के आचरण से नहीं बढ़ाया होता तो यह उतना गंभीर मोड़ नहीं लेता जितना उसने लिया था। फिर आपसी उकसावा और उत्तेजना होती है, और प्रत्येक योद्धा के लिए दोष के हिस्से को विभाजित करना मुश्किल होता है। अपवाद 4 की सहायता तब ली जा सकती है जब मृत्यु (क) पूर्वकल्पना के बिना, (ख) अचानक लड़ाई में (ग) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना और (घ) लड़ाई मारे गए व्यक्ति के साथ हुई होगी। (पैरा 12), (805-जी-एच; 806-ए-डी),

3.3 . एक मामले को अपवाद 4 के भीतर लाने के लिए इसमें उल्लिखित सभी सामग्री इसे खोजना ही होगा। आई. पी. सी. की धारा 300 के अपवाद 4 में होने वाली लड़ाई को आई. पी. सी. में परिभाषित नहीं

किया गया है। लड़ाई करने में दो लोग लगते हैं। जुनून की गर्मी के लिए आवश्यक है कि जुनून को ठंडा करने के लिए कोई समय नहीं होना चाहिए और इस मामले में, पार्टियों ने शुरुआत में मौखिक विवाद के कारण खुद को क्रोधित कर लिया है। लड़ाई दो और दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक लड़ाई है, चाहे वह हथियारों के साथ हो या बिना हथियारों के। किसी भी सामान्य नियम का उच्चारण करना संभव नहीं है कि अचानक झगड़ा क्या माना जाएगा। यह तथ्य का सवाल है और क्या झगड़ा अचानक होता है या जरूरी नहीं कि यह प्रत्येक मामले के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर करता हो। अपवाद 4 के अनुप्रयोग के लिए, यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्वधारणा नहीं थी। यह आगे दिखाया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूरता से काम नहीं लिया है या असामान्य तरीके से। प्रावधान में प्रयुक्त 'अनुचित लाभ' अभिव्यक्ति का अर्थ है 'अनुचित लाभ'। (पैरा 12), (806-डी-एफ),

3.4. जहाँ अपराधी अनुचित लाभ उठाता है या उसने क्रूरतापूर्ण कार्य किया है या असामान्य तरीके से, उसे अपवाद 4 का लाभ नहीं दिया जा सकता है। अगर हमलावर द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार या हमले का तरीका सभी अनुपातों से बाहर है, यह तय करने के लिए कि क्या

अनुचित लाभ उठाया गया है, उस परिस्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। (पैरा 13), (806-जी-एच),

किकर सिंह बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर (1993) एससी 2426, संदर्भित।

3.5. उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में तथ्यों पर विचार कर अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि आईपीसी की धारा 300 का अपवाद 4 लागू होता है और अपराध आईपीसी की धारा 304 भाग प् से संबंधित है न कि आईपी सी की धारा 302 से। ऐसा होने पर, दोषसिद्धि बदली जाती है। 10 साल की अभिरक्षा की सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी। (पैरा 14), (807-बी),

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं. 1172/2007.

कलकत्ता उच्च न्यायालय के सी.आर.ए. सं. 228/2004 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 30.01.2006 से।

डॉ. सुधाकर चैधरी, बिनय कुमार झा और रामेश्वर प्रसाद गोयल अपीलार्थी के लिए।

अविजीत भट्टाचार्जी उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था।

डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, द्वितीय न्यायालय, मालदा द्वारा सैशन विचारण सं. 51/2001 में भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में आईपीसी) की धारा 302 के तहत सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को कलकत्ता उच्च न्यायालय की पीठ ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा के निर्णय को चुनौती दी गई हैं।

3. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैंः

13.02.1994 को लगभग दोपहर 2ः30 बजे भारती मंडल नामक एक युवा लड़की सिर पर 'खरी' का बंडल लिए घर लौट रही थी। जैसे ही अपीलार्थी कुलेश मंडल के शरीर पर 'खरी' लगी, आरोपी नरेश मंडल (उच्च न्यायालय द्वारा बरी) और उसके भाई अपीलार्थी-कुलेश मंडल ने उस पर गंदी भाषा का प्रयोग किया। अभियुक्त के इस तरह के व्यवहार से हैरान, सूचनाकर्ता नरेन मंडल ने अपना कड़ा विरोध जताया। उनके बीच नोकझोंक हो गई। इसके बाद सूचनाकर्ता पर ईंटें फेंकी गईं। जब इस तरह की चीजें चल रही थीं, एक चक्कू मंडल (जिसे इसके बाद मृतक कहा जाता है) सड़क के किनारे से गुजर रहा था। वह यह पूछने के लिए मौके पर आया कि वहां क्या चल रहा था। उसे वहाँ पाकर, आरोपी नरेश मंडल उसे घसीटते हुए घटना स्थल पर ले गया और उसके भाई अपीलार्थी कुलेश मंडल ने उसकी गर्दन पर 'हसुआ' से घातक प्रहार किया। घायल चक्कू मंडल की गर्दन पर

गंभीर चोट लगने के कारण, उसे अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया गया। दुर्भाग्य से, घायल ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया।

सूचनाकर्ता नरेन मंडल ने घटना की सूचना स्थानीय पी. एस. मानिकचक पी. एस. मामला सं. 10/1994 दिनांक 13.02.1994 अन्तर्गत धारा 341/323/302/34 के तहत कुलेश मंडल और अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया था। शव की जांच के बाद जांच अधिकारी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मालदा सदर अस्पताल भेज दिया। जाँच अधिकारी द्वारा घटना स्थल का एक रेखाचित्र मानचित्र तैयार करने के साथ जाँच सामान्य तरीके से आगे बढ़ी। उन्होंने खून से सना मिट्टी को भी जब्त कर लिया, नियंत्रण मिट्टी, टूटी हुई टाइलों और ईंटों के कुछ टुकड़े, कुछ सूखे लकड़ी और गवाहों की उपस्थिति में जब्त सूची तैयार की गई। इसके बाद पीड़ित के खून से सने परिधान भी जब्त कर लिए गए। दोषियों को पकड़ने के लिए, छापेमारी के बावजूद, आरोपी व्यक्ति लंबे समय तक गिरफ्तारी से बच गए। आखिरकार, उन्हें एक के बाद एक गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी कुलेश मंडल की गिरफ्तारी केवल 18.6.1994 पर ही की जा सकी। इस बीच, जाँच अधिकारी ने उपलब्ध गवाहों से पूछताछ की। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत दर्ज भारती मंडल का बयान (संक्षेप में 'द.प्र.सं.') प्राप्त किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी प्राप्त किया गया था। अनुसंधान पूर्ण होने पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

मामले की सुपुर्दगी के बाद, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी और अन्य के खिलाफ आईपी सी की धारा 302/34, 323/34 और 337/34 के तहत आरोप तय किए। अभियुक्त व्यक्तियों ने बेगुनाही स्वीकार करने के बाद, अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने के लिए 14 गवाहों से परीक्षित करवाया। उल्लेखनीय गवाहों में घटना के चश्मदीद गवाह, अभियोगी वस्तुओं की जब्ती के गवाह, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और मामले की अनुसंधान करने वाले अधिकारी शामिल थे। भारती मंडल का बयान दर्ज करने वाले विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट से भी अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में परीक्षित कराया। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और सहायक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पूरा भरोसा रखते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता कुलेश मंडल और उसके भाई को आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया। विचारण न्यायालय ने साक्ष्य को विश्वसनीय और ठोस पाया और इसलिए, दोनों आरोपी व्यक्तियों को आईपीसी की धारा 34 के साथ सपठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी पाया। उन्हें आजीवन कारावास और रूपए 5000/- प्रत्येक के जुर्माने की सजा सुनाई गई, अदम अदायगी जुर्माने में, छह महीने के लिए कठोर कारावास। हालाँकि, दोनों अभियुक्त व्यक्ति आईपीसी की धारा 323/34 और 337/34 के तहत आरोपों से बरी किए थे। चार अन्य आरोपी राधिक

मंडल, अनिल मंडल, उत्तम मंडल और दीपेन मंडल को बरी कर दिया गया, क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त सामग्री नहीं पाई गई थी।

आईपीसी की धारा 302/34 के तहत दोषसिद्धि और सजा से व्यथित, दोनों दोषी अभियुक्त व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की।

4. उच्च न्यायालय के समक्ष प्राथमिक स्थिति यह थी कि रिश्तेदारों का साक्ष्य विश्वास नहीं किया जाना चाहिए था, आरोपी नरेश मंडल को दोषी ठहराने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था और घटना में किसी भी दशा में धारा 302 लागू नहीं होती हैं। उच्च न्यायालय ने किसी भी तर्क में कोई सार नहीं पाया और अपील को खारिज कर दिया।

5. वर्तमान अपील के समर्थन में अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील तर्क प्रस्तुत किया कि तथाकथित चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वे मृतक से संबंधित हैं। घटना में झगड़े के दौरान केवल एक ही वार किया गया था और इसलिए, किसी भी दशा में आईपीसी की धारा 302 लागू नहीं होती है।

6. दूसरी ओर राज्य के विद्वान वकील ने आदेश का समर्थन किया।

7. हम यह भी देख सकते हैं कि गवाह निकट रिश्तेदार होने और परिणामस्वरूप पक्षपाती गवाह होने पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए,

इसका कोई आधार नहीं है। इस सिद्धांत को इस अदालत ने दलीप सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, एआईआर (1953) एस. सी. 364 में खारिज कर दिया था। जिसमें बार के सदस्यों के मन में इस धारणा पर आश्चर्य व्यक्त किया गया था कि रिश्तेदार स्वतंत्र गवाह नहीं थे। विवियन बोस, जे. के माध्यम से बोलते हुए यह देखा गयाः

> "हम उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों से सहमत होने में असमर्थ हैं कि दो चश्मदीद गवाहों की गवाही के लिए पुष्टि की आवश्यकता है। अगर इस तरह के अवलोकन की नींव इस तथ्य पर आधारित है कि गवाह महिलाएँ हैं और सात पुरुषों का भाग्य उन पर लटकता है गवाही, हम ऐसे किसी नियम के बारे में नहीं जानते हैं। यदि यह कारण पर आधारित है कि वे मृतक के निकट संबंधी हैं, हम सहमत होने में असमर्थ हैं। यह कई आपराधिक मामलों में एक आम भ्रांति है और जो इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने इस मामले को खारिज करने का प्रयास किया - रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य एआईआर (1952) एससी 54 पी 59। लेकिन हम पाते हैं कि यह दुर्भाग्य से अभी भी बना हुआ है, यदि न्यायालयों

के निर्णयों में नहीं है, किसी भी तरह से वकील के तर्कों में।"

8. फिर से मसालती और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर (1965) एस. सी. 202 इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः (पी 209-210 पैरा 14)ः

> "लेकिन हम सोचते हैं कि यह तर्क देना अनुचित होगा कि गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य को केवल इस आधार पर खारिज किया जाना चाहिए कि पक्षपाती या हितबद्ध गवाहों की साक्ष्य है। .... यांत्रिक आधार पर इस तरह के साक्ष्य की अस्वीकृति कि यह पक्षपातपूर्ण है यह हमेशा न्याय की विफलता का कारण बनेगा। साक्ष्य की कितनी विवेचना की जानी चाहिए, इसके बारे में कोई सख्य नियम नहंी बनाया जा सकता हैं। इस तरह के साक्ष्य से निपटने में न्यायिक दृष्टिकोण को सर्तक रहना होगा। लेकिन यह तर्क कि इस तरह के साक्ष्य को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह पक्षपातपूर्ण है, इसे सही नहीं माना जा सकता है।"

9. पंजाब राज्य बनाम जागीर सिंह एआईआर (1973) एससी 2407 और लेहना बनाम हरियाणा राज्य, (2002), 3 एससीसी 76 मामले में भी

यही निर्णय लिया गया है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम श्रीमती. कल्कि और अन्य, एआईआर (1981) एस. सी. 1390, में अभिनिर्धारित किया गया। साक्ष्य में सामान्य विसंगतियां वे हैं जो अवलोकन की सामान्य त्रुटियों, समय बीतने के कारण स्मृति की सामान्य त्रुटियों, घटना के समय सदमे और भय जैसे मानसिक स्वभाव के कारण होती हैं और वे हमेशा होती हैं, हालांकि, एक ईमानदार और सच्चा गवाह हो सकता है। सारभूत विसंगतियाँ वे हैं जो सामान्य नहीं हैं, और एक सामान्य व्यक्ति से अपेक्षित नहीं हैं। अदालतों को उस श्रेणी को चिह्नित करना होगा जिसमें विसंगति को वर्गीकृत किया जा सकता है। जबकि सामान्य विसंगतियाँ विश्वसनीयता को खराब नहीं करती हैं किन्तु, सारभूत विसंगतियां ऐसा करती हैं। इन पहलुओं को कृष्ण मोची और अन्य बनाम बिहार राज्य आदि, जे. टी. (2002) 4 एससी 186 में उजागर किया गया था।

10. शेष तर्क अपवाद 4 की प्रयोज्यता से संबंधित है। आईपीसी की धारा 300, जैसा कि यह तर्क दिया जाता है कि घटना अचानक झगड़े के क्रम में हुई थी।

11. इसके संचालन में लाने के लिए यह स्थापित करना होगा कि कार्य बिना पूर्व-चिंतन के प्रतिबद्ध, अचानक लड़ाई में आवेश के वेग में

अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना अचानक हुए झगड़े पर और क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया।

12. आईपीसी की धारा 300 के चैथे अपवाद में अचानक लड़ाई में किए गए कार्य शामिल हैं। उक्त अपवाद अभियोजन के मामले से संबंधित है जो पहले अपवाद के दायरे में नहीं आता है, जिसके बाद इसका स्थान अधिक उपयुक्त होता। अपवाद एक ही सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोनों में है पूर्व-चिंतन का अभाव हैं। लेकिन, जबकि अपवाद 1 के मामले में आत्म-नियंत्रण का पूर्ण अभाव है, अपवाद 4 के मामले में, केवल वह आवेश का वेग हैं, जो पुरुषों के शांत विचार को प्रभावित करता है और उन्हें ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित करता है जो अन्यथा वे ऐसा नहीं करेंगे। अपवाद 4 में उत्तेजना है, जैसा कि अपवाद 1 में है। लेकिन, की गई चोट उस उत्तेजना का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। वास्तव में अपवाद 4 उन मामलों से संबंधित है जिनमें भले ही कोई आघात लगा हो, या विवाद की उत्पत्ति में कोई उत्तेजना दी गई हो या किसी भी तरह से झगड़ा उत्पन्न हुआ हो, फिर भी दोनों पक्षों का बाद का आचरण उन्हें अपराध के संबंध में समान आधार पर रखता है। एक 'अचानक लड़ाई' का अर्थ है आपसी उकसावे और दोनों पक्षों पर मार-पीट। तब की गई हत्या का स्पष्ट रूप से एकतरफा उकसावे के लिए पता नहीं लगाया जा सकता है, न ही ऐसे मामलों में पूरे दोष को एक तरफ रखा जा सकता है। यदि ऐसा था, तो

अधिक उचित रूप से लागू होने वाला अपवाद अपवाद 1 होगा। लड़ने के लिए कोई पूर्व विचार-विमर्श या दृढ़ संकल्प नहीं है। अचानक एक लड़ाई होती है, जिसके लिए दोनों पक्षों को कमोबेश दोषी ठहराया जाता है। यह हो सकता है कि उनमें से एक ने इसे शुरू किया हो, लेकिन अगर दूसरे ने इसे अपने स्वयं के आचरण से नहीं बढ़ाया होता तो यह उतना गंभीर मोड़ नहीं लेता जितना उसने लिया था। तब आपसी उत्तेजना और उत्तेजना होती है, और इसके हिस्से को विभाजित करना मुश्किल होता है। दोष जो प्रत्येक योद्धा से जुड़ा होता है। अपवाद 4 की मदद ली जा सकती है। यदि मृत्यु हो जाती है (ए) बिना पूर्व-चिंतन के, (बी) अचानक लड़ाई में (सी) अपराधी के अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य रूप से कार्य किए बिना तरीका के और (घ) लड़ाई मारे गए व्यक्ति के साथ हुई होगी। एक मामले को अपवाद 4 के भीतर लाने के लिए उसमें उल्लिखित सभी अवयवों को पाया जाना चाहिए। आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 में होने वाली 'लड़ाई' आईपीसी में परिभाषित नहीं है। लड़ाई करने में दो लोग लगते हैं। आवेश के वेग के लिए आवश्यक है कि आवेश को ठंडा करने के लिए कोई समय नहीं होना चाहिए और इस मामले में, पार्टियों ने शुरुआत में मौखिक विवाद के कारण खुद को क्रोधित कर लिया है। लड़ाई दो और दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक लड़ाई है, चाहे वह हथियारों के साथ हो या बिना हथियारों के। किसी भी सामान्य नियम का प्रतिपादन करना संभव नहीं है कि अचानक झगड़ा क्या माना जाएगा। यह तथ्य का सवाल

है और क्या झगड़ा अचानक होता है या नहीं, यह आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर करता है। अपवाद 4 के अनुप्रयोग के लिए, यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्वचिंतन नहीं था। यह आगे दिखाया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया है। प्रावधान में प्रयुक्त 'असम्यक लाभ' अभिव्यक्ति का अर्थ है 'अनुचित लाभ'।

13. जहाँ अपराधी अनुचित लाभ उठाता है या उसने क्रूरतापूर्ण कार्य किया है या असामान्य तरीके से, उसे अपवाद 4 का लाभ नहीं दिया जा सकता है। यदि हमलावर द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार या हमले का तरीका सभी अनुपात से बाहर है, तो यह तय करने के लिए कि क्या अनुचित लाभ उठाया गया है, उस परिस्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। किकर सिंह बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर (1993) एससी 2426 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि अभियुक्त ने निहत्थे व्यक्ति के खिलाफ घातक हथियारों इस्तेमाल किया और सिर पर एक वार किया, तो यह माना जाना चाहिए कि उसने यह जानते हुए वार किया कि उसने मृत्यु का कारण बनने की संभावना थी, उसने अनुचित लाभ उठाया हैं।

14. उपर निर्धारित सिद्धांत के आलोक में पृष्ठभूमि तथ्यों पर विचार करते हुए अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि धारा 300 का अपवाद 4 लागू होता है और अपराध आईपीसी की धारा 304 भाग प् से संबंधित है, न कि आईपीसी की धारा 302 से। ऐसा होने पर, दोषसिद्धि बदल जाती है, अभिरक्षा के 10 वर्षों की सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी।

15. अपील की अनुमति उपरोक्त सीमा तक दी जाती है।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी महेन्द्र कुमार टांक (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।